टेकाबा एओ और अन्य

बनाम

सकुमरेन एओ और अन्य

अप्रैल 29,2004

[शिवराज वी. पाटिल और डी.एम. धर्माधिकारी, जे.जे.]

प्रथागत कानूनः

नागालैंड में न्याय और पुलिस प्रशासन के लिए नियम, 1937 - नियम 29 और 62 (2) - पहाड़ी जिले के दो गाँवों के दो कुलों के बीच विवाद - जल स्रोत तक पहुँच और भूमि के स्वामित्व के संबंध में जिसमें स्रोत मौजूद है - प्रथागत न्यायालयों द्वारा फैंसला - उच्च न्यायालय में अपील - उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य दर्ज करने और एक कबीले के खिलाफ मूल न्यायालय के रूप में दर्ज साक्ष्य पर मामला तय करने के लिए भूमि के स्वामित्व पर अतिरिक्त मुद्दे को जिला प्रथागत न्यायालय को प्रेषित करना - अपील पर निर्धारितः ग्राम न्यायालयों में प्रथागत कानून लागू किया जाता है और विवाद को आपसी सहमति और सर्वसम्मति से हल किया जाता है – भूमि के स्वामित्व के विवाद को पहली बार एक ही कबीले के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय द्वारा तय करने की कवायद करना नियमों के अक्षरशः और भावना के अनुरूप नहीं है – साथ ही पक्ष को भेजे गए अतिरिक्त मुद्दे के संबंध में नए सिरे से अभिवचन दायर करने

की अनुमति नहीं है जिसके परिणामस्वरूप पक्ष के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होता है - इसलिए, उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है – घोषणा पारित की गई कि विवादित भूमि में जल स्रोत पर दोनों पक्षों का संयुक्त और समान अधिकार होगा और किसी भी कबीले का कोई भी सदस्य दोनों ग्राम समुदायों में से किसी एक तक पहुंच को प्रतिबंधित नहीं करेगा - स्वामित्व का विवाद भविष्य में नियमों के अनुसार उठाए जाने पर निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

पहाड़ी जिले के दो गाँवों की गाँव की सीमाओं का सीमांकन स्तंभों को खड़ा करके किया गया था। दो गाँवों के एस और पी कुलों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। अपीलार्थियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एस कबीले ने आरोप लगाया कि प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पी कबीले के सदस्यों ने स्तंभों को हटा दिया और जल स्रोत के उपयोग के लिए विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई। ग्राम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जिस विवादित भूमि में जल स्रोत स्थित है, अपीलार्थियों की है। प्रत्यर्थियों ने एक अपील दायर की। इसके बाद नियम 24(1) को नागालैंड में न्याय और पुलिस प्रशासन के लिए नियम, 1937 में शामिल किया गया, जिसमें सिविल प्रकृति के विवाद में पक्षों द्वारा अभिवचन दायर करने का प्रावधान था। अपीलार्थियों ने एक लिखित बयान पेश किया। उठाये गए विवादों पर विवाधक तैयार किये गए, लेकिन भूमि के स्वामित्व के संबंध में नहीं जिसमें जल स्रोत मौजूद था।

अपीलीय प्राधिकारी ने अपील को स्वीकार कर लिया और जल स्रोत और भूमि दोनों पर प्रत्यर्थी का अधिकार घोषित कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की। एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों के इस तर्क को स्वीकार किया कि भूमि के स्वामित्व पर विवाधक तैयार किए बिना, भूमि के संबंध में विवाद का फैसला नहीं किया जा सकता था और भूमि के स्वामित्व पर मुद्दे को अपीलीय प्राधिकरण को प्रतिप्रेषित किया गया, जिसने अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज किया और इसे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि भूमि का स्वामित्व प्रत्यर्थियों के पास है। इसलिए वर्तमान अपील।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 नागालैंड में न्याय और पुलिस प्रशासन के नियम, 1937 में नागालैंड के पहाड़ी जिलों पर लागू होने वाले विशिष्ट मूल और प्रक्रियात्मक कानून को ध्यान में रखते हुए, गांव का विवाद, विशेष रूप से पानी के स्रोत और उस भूमि के संबंध में जिसमें यह स्थित है, को दो प्रतिस्पर्धी कुलों के सदस्यों के परस्पर विरोधी अधिकारों के समायोजन और समायोजन की भावना से समाधान की आवश्यकता वाले विषय के रूप में निर्णय लेने की आवश्यकता थी, न कि प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में। ग्राम न्यायालयों में प्रथागत कानून लागू करने की आवश्यकता होती है और न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में न्यायनिर्णयन मंचों को आपसी सहमति से विवाद

को सुलझाने और आम सहमति हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान विवाद को एक समाधान की आवश्यकता थी ताकि दो ग्राम समुदायों के उन सभी सदस्यों की मांगों को सर्वोत्तम ढंग से पूरा किया जा सके जिन्होंने विवाद उठाया था। भूमि और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक अधिकारों के प्रयोग से संबंधित विवादों में ग्रामीण कभी भी एक या दूसरे पक्ष के पक्ष में ऐसे विवादों के मात्र औपचारिक निर्णय से संतुष्ट महसूस नहीं कर सकते हैं। निर्णय के बजाय उन्हें अपने पारस्परिक लाभ के लिए ऐसे विवादों का संतोषजनक समाधान चाहिए। [904-सी-एफ]

1.2. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उस भूमि के स्वामित्व के मुद्दे को, जिसमें जल स्रोत मौजूद है, अतिरिक्त मुद्दे पर साक्ष्य दर्ज करने और ऐसे साक्ष्यों पर मामले का निर्णय करने के लिए जिला प्रथागत न्यायालय को भेजकर, वस्तुतः मूल न्यायालय के रूप में कार्य किया है। विवाद को पहले ग्राम न्यायालय में आम सहमति पर पहुंचने के सभी प्रयासों के साथ सहयोग की भावना से निपटाया जाना आवश्यक है और फिर, यदि आवश्यक हो, तो अपील के माध्यम से जिला न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विवाद का निर्णय लेने के बाद पीड़ित पक्ष द्वारा अपील के माध्यम से मामले को उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने ग्राम न्यायालय को प्राथमिक न्यायालय के रूप में दो गांवों के दो गुटों के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण

और आम सहमति से सुलझाने का प्रयास करने से वंचित कर दिया है। भूमि के स्वामित्व के उक्त विवाद को पहली बार अपील में उच्च न्यायालय द्वारा तय करने की कवायद नियमों के अक्षरशः और भावना के अनुरूप नहीं थी। [905-ए-सी]

1.3. जब उच्च न्यायालय ने स्वामित्व के अतिरिक्त मुद्दे पर साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले को जिला ग्राम न्यायालय को भेज दिया, तो पक्षों द्वारा अभिवचन दायर करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पक्षों को अतिरिक्त मुद्दे के संबंध में नई याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी। इसने अपीलार्थियों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया क्योंकि वे अपील के जवाब में दायर अपने लिखित बयानों में प्रत्यर्थियों के स्वामित्व के दावे का खंडन नहीं कर सके और स्वामित्व के ऐसे मुद्दे का फैसला उनके खिलाफ किया गया। इसलिए, भूमि के स्वामित्व के अतिरिक्त मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त किया जाता है। [905-डी-एफ]

1.4. गाँव समुदाय का विवाद विशेष रूप से पहुँच से संबंधित जल स्रोत वाली भूमि एक पारंपरिक दीवानी मुकदमा नहीं है जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सामान्य दीवानी अदालतों द्वारा संभाला जाता है। ये ऐसे विवाद हैं जिन्हें केवल ग्रामीण समुदायों के रीति-रिवाजों के आधार पर और नियमों में निहित एक बहुत ही अनौपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। जहां तक भूमि और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों

का सवाल है, स्वामित्व का विवाद बहुत प्रासंगिक नहीं है क्योंकि निस्संदेह राज्य संप्रभु प्रमुख स्वामी है। [906-ए-सी]

1.5. विवाद के विषय की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए, जिसमें पक्षकारों पर लागू प्रथागत कानून पर निर्णय की आवश्यकता होती है, पक्षकारों को भूमि के स्वामित्व के मुद्दे पर मुकदमा चलाने की फिर से अनुमति देना आवश्यक नहीं है। लंबे समय बीतने और अधिवक्ता के पास नवीनतम जानकारी और निर्देश नहीं होने को ध्यान में रखते हुए, यह घोषित किया जाता है कि दो गांवों के दो कुलों को विवादित भूमि में जल स्रोत पर संयुक्त और समान अधिकार होगा और उनमें से कोई भी दो गाँव समुदायों में से किसी एक को सामान्य जल स्रोत तक पहुँच से प्रतिबंधित नहीं करेगा। भूमि के स्वामित्व के संबंध में विवाद को 1937 के नियमों के संदर्भ में सक्षम ग्राम न्यायालय द्वारा तय करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है, यदि भविष्य में विवाद उत्पन्न होते हैं। [906 - सी-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2196/1999

एफ.ए. संख्या 1(के)/1993 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय कोहिमा पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 27.2.97 से।

शिवाजी एम्.जाधव, (एनपी), अपीलार्थियों की और से।

एस.बी.सान्याल, राजीव मेहता और बी.अगर्वल्ला, प्रत्यार्थियों की और से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया

धर्माधिकारी, न्यायाधिपति

यह अपील नागालैंड के उत्तर-पूर्वी राज्य में मोकोकचुंग के पहाड़ी जिले में दो गाँवों के दो कुलों के बीच विवाद से उत्पन्न होती है। दोनों गाँवों के दो कुलों के बीच विवाद पानी के स्रोत तक पहुँच और वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व से संबंधित है जिसे अपीलार्थियों द्वारा 'जाकोक्तसुबा' और प्रत्यार्थियों द्वारा 'मेज़ेंटेराब' के रूप में वर्णित किया गया है। अधिक विवरण में जाए बिना, यह कहना पर्याप्त है कि यहाँ अपीलकर्ता लोंगखुम गाँव के साई (सोया) कबीले का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्यर्थीगण मंगमेटोंग गाँव के पोंगेन कबीले का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जल स्रोत और भूमि को लेकर विवाद वर्ष 1985 में तब उत्पन्न हुआ जब दोनों गांवों के सीमा स्तंभों को कुछ ग्रामीणों द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया गया था।

शुरुआत में, यह कहा जा सकता है कि नागालैंड के पहाड़ी जिले में जल स्रोत और भूमि के नागरिक अधिकार, जिसमें ऊपर वर्णित दो गांव शामिल हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में निहित किसी भी संहिताबद्ध कानून द्वारा शासित नहीं हैं। पक्षकार नागालैंड के पहाड़ी जिले की आदिवासी और ग्रामीण आबादी पर लागू प्रथागत कानून द्वारा शासित होते हैं। अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 की धारा 6 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम के राज्यपाल द्वारा नागालैंड में न्यायिक और

पुलिस प्रशासन के लिए नियम, 1937 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) तैयार करके प्रथागत कानून को मान्यता दी गई है। उपरोक्त नियमों को वर्ष 1984 और 1989 में संशोधित किया गया था। सिविल न्याय प्रणाली न्यायालयों के पदानुक्रम का प्रावधान करती है। सबसे निचले मूल ग्राम न्यायालय को 'डोभासिस' कहा जाता है, जो उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त या उपायुक्त के सहायक, जैसा भी मामला हो, द्वारा संदर्भित नागरिक मामलों की सुनवाई और निर्णय कर सकता है। डोभासिस न्यायालय में मौजादार गांवबुरा जैसे गांव के प्राधिकारी, खेल के प्रमुख और मुखिया और गांव के अन्य बुजुर्ग शामिल होते हैं। डोभासिस या ग्राम न्यायालय में प्रक्रिया कम औपचारिक है। कार्यवाही मौखिक होती है। अपनी-अपनी पंचायतों के निर्णय का पालन करने के लिए नियमों के तहत प्रयास करना आवश्यक है। जिला प्रथागत न्यायालय में अपील प्रदान की जाती है और नियम 29 के तहत उच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की जा सकती है। नियम 62(2) इन ग्राम न्यायालयों और प्रथागत न्यायालयों की प्रक्रिया निम्नानुसार प्रदान करता है:

> "**नियम 62(2).** सिविल मुकदमों का निर्णय करने में जिला प्रथागत न्यायालय और अधीनस्थ जिला प्रथागत न्यायालय ऐसे मुकदमों और मामलों पर लागू रीति-रिवाजों और प्रथाओं का पालन करेंगे और ऐसे सभी मुकदमों और मामलों का न्याय, समानता, अच्छे विवेक

और लागू रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार फैसला करेंगे।"

उक्त नियम का उप-नियम (3) इस प्रकार है-

"**नियम 62(3).** जिला प्रथागत न्यायालय और अधीनस्थ जिला प्रथागत न्यायालय सिविल मुकदमों का निर्णय करने में प्रक्रिया के मामलों में जिले में पालन किए जाने वाले रीति-रिवाजों और प्रथाओं के दायरे में नहीं आने वाले मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता की भावना का पालन करेंगे।"

प्रथागत कानून को मान्यता देने और आदिवासियों और ग्रामीणों के बीच विवादों को हल करने के लिए अधीनस्थ प्रथागत अदालत और जिला अदालत के मंच प्रदान करने वाले उपर्युक्त 1937 नियमों में 14.3.1989 को नियम 24(1) को शामिल करके संशोधन किया गया, जो नागरिक प्रकृति विवाद में पक्षों द्वारा याचिका दायर करने की सुविधा प्रदान करता है।

विवाद की संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः-

कहा जाता है कि संबंधित दो गाँवों की सीमा का वर्ष 1942 में स्तंभों को खड़ा करके सीमांकन किया गया। लगभग 2 एकड़ भूमि और उसमें उपलब्ध जल स्रोत के संबंध में विवाद कथित तौर पर वर्ष 1985 में उत्पन्न हुए थे, जब अपीलकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने देखा कि गाँव में

प्रत्यर्थियों के प्रतिनिधित्व वाले कबीले के सदस्यों ने जल स्रोत के उपयोग के लिए खंभों को हटा दिया और विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया। अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष 3.5.1985 पर शिकायत दर्ज की, जिन्होंने ग्राम प्रथागत न्यायालय अर्थात दोभासिस कोर्ट में निर्णय के लिए विवाद का समर्थन किया।

दोभासिस न्यायालय गवाहों से पूछताछ करने और घटनास्थल का सत्यापन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विवादित भूमि जिसमें जल स्रोत स्थित है, अपीलार्थियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लोंगखुम गाँव के साई कबीले की है।

प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए ग्रामीण 12.12.1985 को अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक) के पास अपील में गए। उन्होंने अतिरिक्त उपयुक्त द्वारा डेनोवो परीक्षण के लिए भी प्रार्थना की।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उस समय जब विवाद को उत्पन्न करते हुए शिकायत दर्ज की गई थी, अभिवचनों को सख्ती से नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं था। अभिवचन दाखिल करने की आवश्यकता वाला प्रावधान वर्ष 1989 में बनाए गए नियमों में संशोधन द्वारा पेश किया गया था। अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष, अपीलार्थियों ने प्रत्यर्थियों द्वारा दायर अपील पर एक लिखित बयान प्रस्तुत किया था। अतिरिक्त उपायुक्त ने ग्रामीणों द्वारा उठाए गए विवादों पर आठ विवाधक तैयार किए, लेकिन जिस भूमि में जल स्रोत मौजूद है, उसके स्वामित्व के

संबंध में कोई विवाधक परीक्षण के लिए तैयार नहीं किया गया था। अतिरिक्त उपायुक्त ने जल स्रोत के विवाद के सम्बन्ध में मुद्दों पर सुनवाई करने के बाद, प्रत्यर्थियों की अपील को स्वीकार कर लिया और जल स्रोत के साथ-साथ विवादित भूमि दोनों पर उनका स्वामित्व घोषित किया।

अतिरिक्त उपायुक्त के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ में अपील की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि भूमि के स्वामित्व पर मुद्दा बनाए बिना, भूमि के संबंध में विवाद का निर्णय अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने 20.6.1996 को एक आदेश पारित कर भूमि के स्वामित्व पर एक अतिरिक्त मुद्दे को उस मुद्दे पर साक्ष्य दर्ज करने और अपील पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय के साक्ष्य के रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त को भेज दिया। तैयार किया गया अतिरिक्त मुद्दा इस प्रकार है:-

> "क्या वादी या प्रतिवादी विवादित भूमि का मालिक है
> और उसके पास मैंगमेटोंग और लोंगखुम गांवों के बीच
> स्थित लगभग 2 एकड़ विवादित भूमि है।"

इसके बाद, अतिरिक्त उपायुक्त ने अतिरिक्त मुद्दे पर पक्षों के अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज किए और उच्च न्यायालय को साक्ष्य का अभिलेख प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अतिरिक्त मुद्दे पर

दर्ज अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ अपील का फैसला किया। चूंकि अतिरिक्त साक्ष्य अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा दर्ज किया गया था और उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था, इसलिए भूमि के स्वामित्व के मुद्दे पर निर्णय लेने में उच्च न्यायालय ने मूल न्यायालय के रूप में कार्य किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थियों द्वारा दावा की गई विवादित भूमि के स्वामित्व से वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा लिखित बयान में विशेष रूप से इनकार नहीं किया गया था, जिसे उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष अपील में प्रस्तुत किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अन्य गवाहों के साक्ष्य का भी उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि भूमि वन भूमि थी। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य को बहुत महत्व दिया कि प्रत्यर्थी अपीलार्थियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए ग्रामीणों से बिना किसी आपत्ति के वन उपज एकत्र करके भूमि पर स्वामित्व के अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे। इसने गवाहों के बयान का भी संदर्भ दिया कि कुलों के बीच प्रचलित प्रथा के अनुसार, जब भी, अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कबीले के सदस्य जल स्रोत का उपयोग करते थे, तो कबीले के सदस्यों के लिए एक चाय पार्टी रखी जाती थी। प्रत्यर्थियों ने दूसरे कबीले पर जल स्रोत के स्वामित्व की मान्यता का संकेत दिया। उपरोक्त आधारों पर और पक्षों के मौखिक साक्ष्यों की सराहना करते हुए, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विवादित भूमि का स्वामित्व प्रत्यर्थियों के पास है।

वर्तमान अपील में, आवश्यक निर्देशों के अभाव में, अपीलार्थियों द्वारा नियुक्त विद्वान अधिवक्ता इस अपील के निर्णय में न्यायालय की सहायता करने में सक्षम नहीं हुए हैं। प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. बी. सान्याल ने दोनों पक्षों के मामले को बहुत निष्पक्षता से रखा और इस न्यायालय द्वारा 2.9.1998 पर पारित आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया। एक ऐसे स्तर पर जब विशेष अनुमति याचिका पर केवल विरोधी पक्ष को केवल नोटिस जारी किया गया था, इस न्यायालय ने 2.9.1998 को अपने आदेश में अपीलार्थियों की ओर से दिया गया बयान इस प्रकार दर्ज कियाः

> 'याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निर्देशों पर कहा कि याचिकाकर्ताओं को किसी भी समय इस विवादित जलमार्ग से किसी भी मात्रा में पानी लेने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते कि केवल एक ही व्यक्ति को औपचारिक रूप से स्वीकार करना पड़े कि उक्त जलमार्ग का स्वामित्व याचिकाकर्ताओं का है। इस कथन पर प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निर्देश लेने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा। आठ सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया।'

इसके बाद, अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए प्रस्तावों के जवाब में निर्देशों की प्रतीक्षा में मामला स्थगित किया जाता रहा। ऐसा प्रतीत होता है

कि अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर कोई निर्देश प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को प्राप्त नहीं हुए थे और इसलिए, अनुमति देने के बाद, इस अपील को 6.4.1999 को दिए गए आदेश द्वारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

यहां तक कि हमारे द्वारा मामले की अंतिम सुनवाई के समय भी, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। हम पहले ही ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता भी निर्देशों के अभाव में इस न्यायालय की सहायता करने में असमर्थ थे। पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीणों की दुर्दशा को अच्छी तरह से महसूस किया जा सकता है क्योंकि इस न्यायालय तक पहुंच उनके लिए बेहद कठिन है। इसलिए, हम अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों और सामग्री के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

मामले के रिकॉर्ड और नियमों का अध्ययन करने के बाद, जो विशेष मंच का गठन करते हैं और नागालैंड राज्य के पहाड़ी जिलों के निवासियों पर लागू पारंपरिक कानून को मान्यता देते हैं, हम पाते हैं कि प्रक्रिया और योग्यता दोनों में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में खामियां हैं।

हमने ऊपर नागालैंड के पहाड़ी जिलों के गाँवों में लागू होने वाले मूल और प्रक्रियात्मक कानून वाले नियमों की प्रकृति का उल्लेख किया है।

पर्वतीय जिलों में रहने वाले लोगों के विवादों का निपटारा करने में न तो सिविल प्रक्रिया संहिता और न ही साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। गाँव के रीति-रिवाजों के आधार पर विवादों का निपटारा करने के लिए उनके पारंपरिक मंच गाँव डोभासिस न्यायालय और जिला ग्राम न्यायालयों का गठन किया गया है। दर्शाई गई प्रक्रिया बिल्कुल भी औपचारिक नहीं है। जिस समय जल स्रोत के संबंध में विवाद उठाया गया था, उस समय नियमों में सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित अभिवचन कानून के सख्त पालन की कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल 1989 में ही नियमों में संशोधन किया गया ताकि दलीलों के कुछ कानून प्रदान किए जा सकें, हालांकि उतने कठोर और कड़े नहीं थे जितने सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित हैं।

नागालैंड के पहाड़ी जिलों पर लागू नियमों में निहित विशिष्ट मूल और प्रक्रियात्मक कानून को ध्यान में रखते हुए, गाँव के विवाद, विशेष रूप से पानी के स्रोत और जिस भूमि पर वह स्थित है, के संबंध में निर्णय लिया जाना आवश्यक था। प्रतिकूल मुकदमेबाजी, लेकिन एक विषय वस्तु के रूप में जिसमें दो प्रतिस्पर्धी कुलों के सदस्यों के परस्पर विरोधी अधिकारों के समायोजन और समायोजन की भावना से समाधान की आवश्यकता होती है। ग्राम न्यायालयों में प्रथागत कानून लागू करने की आवश्यकता होती है और न्यायनिर्णायक प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन मंचों को आपसी सहमति से विवाद को सुलझाने और आम सहमति प्राप्त करने के लिए हर

संभव प्रयास करने की आवश्यकता होती है। गाँवों में पानी के स्रोत तक पहुँच और भूमि के अधिकार और अधिकार के संबंध में वर्तमान मामले में शामिल विवाद, जिसमें स्रोत मौजूद है, के लिए एक समाधान की आवश्यकता थी ताकि दोनों गाँव समुदायों के सभी सदस्यों की मांगों को सर्वोत्तम रूप से पूरा किया जा सके जिन्होंने विवाद उठाया था। भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों में ग्रामीण कभी भी किसी एक या दूसरे पक्ष के पक्ष में ऐसे विवादों के केवल औपचारिक निर्णय से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। निर्णय लेने के बजाय उन्हें अपने आपसी लाभ के लिए ऐसे विवादों के संतोषजनक समाधान की आवश्यकता है।

भूमि के स्वामित्व के मुद्दे को प्रेषित करने की प्रक्रिया को अपनाने में जहाँ जल स्रोत मौजूद है, उच्च न्यायालय ने ग्राम न्यायालय को प्राथमिक न्यायालय के रूप में दोनों गाँवों के दो कुलों के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण और सर्वसम्मति से हल करने का प्रयास करने से वंचित कर दिया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम 55 के तहत, ग्राम न्यायालय के फैसले के खिलाफ, जिला प्रथागत न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विवाद का निर्णय लेने के बाद ही पीड़ित पक्ष द्वारा अपील के माध्यम से मामले को उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अतिरिक्त मुद्दे पर साक्ष्य दर्ज करने और ऐसे साक्ष्य पर मामले का निर्णय करने के लिए स्वामित्व के मुद्दे को जिला प्रथागत न्यायालय को सौंपकर, वस्तुतः मूल न्यायालय के रूप में कार्य किया है। चूँकि विवाद को पहले ग्राम न्यायालय में आम सहमति तक पहुँचने के लिए सभी प्रयासों के साथ सहयोग की भावना से निपटाया जाना आवश्यक है, इसलिए मूल न्यायालय के रूप में भूमि के स्वामित्व के मुद्दे पर निर्णय लेने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उन नियमों के अनुसार नहीं थी जो कम औपचारिक प्रक्रिया और प्रथागत कानून के अनुप्रयोग का प्रावधान करते हैं। भूमि के स्वामित्व के बारे में मुद्दा जिसमें जल स्रोत मौजूद है, यदि बिल्कुल भी महत्वपूर्ण पाया गया था, तो प्राथमिक न्यायालय, यानी ग्राम न्यायालय में उठाए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी और फिर, यदि आवश्यक हो तो एक अपील के माध्यम से जिला न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए था। पहली बार अपील में उच्च न्यायालय द्वारा भूमि के स्वामित्व के उक्त विवाद पर निर्णय लेने का प्रयास करना नियमों के अक्षरशः और भावना के अनुसार नहीं था।

दूसरा दोष जो हम उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय में पाते हैं वह यह है कि उस समय जब उसने स्वामित्व के अतिरिक्त मुद्दे पर साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामला जिला ग्राम अदालत को भेजा था, तो नियमों में संशोधन किया गया था जिसमें पक्षों द्वारा अभिवचन दायर करने का

प्रावधान था। साक्ष्य दर्ज करने के लिए अतिरिक्त मुद्दों को प्रेषित करने के आदेश में, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने पक्षों को अतिरिक्त मुद्दे के सम्बन्ध में नए सिरे से दलीलें दायर करने की अनुमति नहीं दी। इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियों के मामले में गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ क्योंकि जिन आधारों पर उनके खिलाफ स्वामित्व का मुद्दा तय किया गया है, उनमें से एक यह है कि उन्होंने जिला ग्राम न्यायालय के समक्ष विरोधी पक्ष द्वारा दायर अपील के जवाब में दायर अपने लिखित बयानों में उत्तरदाताओं के स्वामित्व के दावे का खंडन नहीं किया है।

उपरोक्त कारण से, हमारी राय में, विवादग्रस्त भूमि के स्वामित्व के अतिरिक्त मुद्दे पर उच्च न्यायालय का निर्णय इस अपास्त किया जाना चाहिए।

जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ताओं के वकील ने विवादित भूमि में स्थित स्रोत से पानी लेने के लिए दूसरे गांव का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तरदाताओं पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है, बशर्ते कि उत्तरदाता दूसरे गांव का प्रतिनिधित्व करें। अपीलकर्ताओं के उक्त जलमार्ग के स्वामित्व को स्वीकार करना चाहिए। इस न्यायालय के आदेश में दिए गए और दर्ज किए गए इस तरह के बयान पर बार-बार समय दिए जाने के बावजूद, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंततः, इसलिए इस अदालत ने अनुमति दे दी और इस अपील पर विचार किया। ग्राहकों

से संचार के आसन साधनों के आभाव में हम देश के ऐसे दूरदराज के कोनों में रहने वाले आदिवासी और गाँव की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता की असहायता को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर कहा है, विशेष रूप से जल स्रोत वाली भूमि तक पहुंच से संबंधित ग्राम समुदाय का विवाद एक पारंपरिक दीवानी मुकदमा नहीं है, जैसा कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत सामान्य दीवानी न्यायालयों द्वारा निस्तारित किया जाता है। ये ऐसे विवाद हैं जिनसे केवल ग्रामीण समुदायों के रीति-रिवाजों के आधार पर और नियमों में निहित एक बहुत ही अनौपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से निपटा जाना चाहिए। जहाँ तक भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संबंध है, स्वामित्व का विवाद बहुत प्रासंगिक नहीं है क्योंकि निस्संदेह राज्य संप्रभु प्रमुख मालिक है।

उपरोक्त परिस्थितियों में और विवाद के विषय की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए पक्षकारों पर लागू प्रथागत कानून पर निर्णय की आवश्यकता है, हम यह आवश्यक नहीं समझते कि पक्षकारों को भूमि के स्वामित्व के मुद्दे पर फिर से मुकदमा करने की अनुमति दी जाए। हमारे सामने आने वाली स्थिति में, जहां विद्वान अधिवक्ता के पास विवाद के विषय पर नवीनतम जानकारी और निर्देश नहीं थे और लंबे समय को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय में इस अपील का यह घोषणा करके निस्तारण किया जा सकता है कि दो गाँवों के दो कुलों में ग्रामीण समुदायों को विवादित भूमि में जल स्रोत पर संयुक्त और समान अधिकार

होगा। दोनों गाँवों में समुदायों के दो प्रतिद्वंद्वी कुलों के सदस्यों में से कोई भी गाँव के दो समुदायों में से किसी एक तक आम जल स्रोत तक पहुँच को इसके बाद प्रतिबंधित नहीं करेगा। दो एकड़ भूमि के स्वामित्व के विवाद पर उच्च न्यायालय के आदेश और उसके निर्णय को अपास्त करने के बाद, हम स्वामित्व के विवाद को किसी भी प्रतियोगी पक्ष द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार इसके समाधान के लिए सक्षम ग्राम न्यायालय में उठाए जाने के लिए खुला रखते हैं, यदि भविष्य में इसके लिए कोई कार्रवाई का कारण बनता है। हालाँकि, हम आशा करते हैं कि कार्रवाई के कारण का ऐसा टकराव कभी पैदा नहीं होगा और भूमि के स्वामित्व के विवाद को उठाए बिना, दोनों ग्राम समुदाय अपने सामान्य लाभ के लिए स्रोत से पानी लेने के अपने अधिकारों को शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से विनियमित करेंगे।

परिणामस्वरूप अपील आंशिक रूप से सफल होती है। ऊपर दिए गए निर्देशों को प्रतिस्थापित करते हुए उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। पक्षों की स्थिति और विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

एन.जे.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

*****